लोग कोरोना से मर रहे थे और मोदी सरकार के मंत्री संपत्ति ख़रीद रहे थे

सुशील मानव

कोरोनाकाल के पहले चरण की शुरुआत अप्रैल 2020 से शुरु होती है। जबकि कोरोना के दूसरे चरण अप्रैल 2021 में लोग बाग ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से बेमौत मरने को अभिशप्त थे। मरीजों की छंटनी के लिये प्राइवेट अस्पताल मॉक ड्रिल कर रहे थे। और जिनके हाथ में लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी मोदी के वो मंत्री संपत्ति ख़रीदने में व्यस्त थे।

पीएमओ की वेबसाइट के अनुसार पिछले साल पहले कोविड के पहले चरण में लॉकडाउन से लेकर 12 महीने की अवधि में, मोदी सरकार के 12 केंद्रीय मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों ने असम से लेकर तमिलनाडु तक कृषि और गैर-कृषि भूमि और दिल्ली में अपार्टमेंट सहित देश भर में संपत्तियां ख़रीदी हैं।

पीएमओ की वेबसाइट पर 12 मंत्रियों द्वारा अप्रैल 2020 से अब तक कृषि भूमि की सात प्रविष्टियों सहित 21 संपत्ति ख़रीद की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के 78 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपत्ति की ख़रीद की घोषणा की, उनमें तीन कैबिनेट मंत्रियों यानि कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और जहाजरानी और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल - और नौ राज्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पांच राज्य मंत्रियों ने अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों में संपत्ति ख़रीदी।

12 मंत्रियों के अलावा, कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह और उनकी पत्नी ने इस अवधि के दौरान दो संपत्तियों की बिक्री की सूचना दी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में घोषित "संपत्ति की लागत" के लगभग चार गुना और छह गुना से अधिक थी।

जयशंकर अपनी घोषणा में दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार में 3.87 करोड़ रुपये में 3,085.29 वर्ग फुट की दूसरी मंजिल का अपार्टमेंट ख़रीदने की सूचना दी। 8 अगस्त, 2020 को ख़रीद की तारीख है, और संपत्ति को "स्वयं" और "पति / पत्नी"दोनों के तहत सूचीबद्ध है।

स्मृति ईरानी की घोषणा में यूपी लोकसभा क्षेत्र अमेठी में संपत्ति की ख़रीद की सूची है। स्मृति ईरानी ने 19 फरवरी, 2021 को मेदान मवई गांव में 12.11 लाख रुपये के "वर्तमान मूल्य" पर 0.1340 हेक्टेयर भूमि का एक टुकड़ा ख़रीदा।

सर्बानंद सोनोवाल ने इस साल फरवरी में डिब्रूगढ़ में तीन संपत्तियों की ख़रीद की सूचना दी है। तब वह असम के मुख्यमंत्री थे। सोनोवाल की घोषणा से पता चलता है कि उन्होंने मनकोट्टा खनिकर मौजा में 6.75 लाख रुपये (1 फरवरी), 14.40 लाख रुपये (23 फरवरी) और 3.60 लाख रुपये (25 फरवरी) में जमीन के तीन पार्सल ख़रीदे।

7 जुलाई, 2021 को, सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री के रूप में शामिल किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की घोषणा से पता चला है कि उन्होंने 2 फरवरी, 2021 को पटना के शिवम अपार्टमेंट में अपना 650 वर्ग मीटर का फ्लैट 25 लाख रुपये में बेचा था। जबकि पिछले साल घोषणा में, उन्होंने "संपत्ति की लागत" को लगभग 6.5 लाख रुपये बताया था।

वहीं गिरिराज सिंह की पत्नी उमा सिन्हा ने अपनी एक संपत्ति - झारखंड के देवघर में 1,087 वर्ग मीटर का घर=45 लाख रुपये में बेच दी। पिछले साल सिंह की घोषणा में, "संपत्ति की लागत" को 7 लाख रुपये "लगभग" के रूप में दिखाया गया था।

9 राज्य मंत्रियों की संपत्ति की ख़रीद का विवरण

पीएमओ की वेबसाइट में वर्तमान में 2013-14 से केंद्रीय मंत्रियों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा शामिल है। राज्य के 45 में से नौ मंत्रियों ने 2020-21 में संपत्ति की ख़रीद की घोषणा की है। इनके विवरण निम्न प्रकार हैं-

श्रीपाद येसो नाइक; बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग- उत्तरी गोवा के उनके निर्वाचन क्षेत्र में तीन संपत्तियां, जिनमें गैर-कृषि भूमि के दो भूखंड और एक आवासीय भवन शामिल हैं। प्लॉट -1286.29 वर्ग फुट (7.23 लाख रुपये) और 188.37 वर्ग फुट (1.08 लाख रुपये) -पैनलिम (सेंट पेड्रो) में स्थित हैं और 27 नवंबर, 2020 को खरीदे गए थे। आवासीय भवन-968.75 वर्ग फुट (40.95 लाख रुपये)— Daugim में है और इसे 8 दिसंबर, 2020 को ख़रीदा गया था।

कृष्ण पाल गुर्जर; हरियाणा में उनके लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में संयुक्त स्वामित्व के माध्यम से कृषि भूमि के तीन पार्सल- भूपानी में 10 अक्टूबर, 2020 को 1.47 करोड़ रुपये में; 31 अक्टूबर, 2020 को भूपानी में 1.95 करोड़ रुपये में; और 24 फरवरी, 2021 को खोरी में 4.21 करोड़ रुपये में।

साध्वी निरंजन ज्योति; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण- 8 जुलाई, 2020 को कानपुर के कृपालपुर में 36.42 लाख रुपये में 1.214 हेक्टेयर भूमि। 2020-21 में संपत्ति ख़रीदने वाले नौ राज्य मंत्रियों में से छह को इस साल 7 जुलाई को हुए फेरबदल में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था। भानु प्रताप सिंह वर्मा; लघु और मध्यम उद्यम- झांसी में बेतवा विहार इलाके में 2021 में 20 लाख रुपये में आवासीय भूखंड।

अन्नपूर्णा देवी; शिक्षा- जुलाई 2020 में झारखंड में अपने लोकसभा क्षेत्र कोडरमा (3.12 लाख रुपये), और रांची (9.75 लाख रुपये) में उनके बेटे द्वारा दो पार्सल ज़मीन की ख़रीद की घोषणा की।

बीएल वर्मा; उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास- बदायूं (यूपी) के उझानी में 3,126.92 वर्ग फुट का प्लॉट 1 जून, 2020 को संयुक्त स्वामित्व में 52 लाख रुपये में, और लखनऊ में मानस एन्क्लेव सोसाइटी में 3,510 वर्ग फुट का प्लॉट संयुक्त स्वामित्व में 70 लाख रुपये में अक्टूबर 7, 2020। वर्मा ने 30 जुलाई, 2020 को बदायूं (यूपी) के बटला खंजन में अपनी पत्नी द्वारा ख़रीदी गई कृषि भूमि की भी घोषणा की है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में भी अपनी पत्नी द्वारा उसी स्थान पर 25 जून को ज़मीन की खरीद को सूचीबद्ध किया है। 2021। वर्मा ने दोनों ख़रीद की संयुक्त लागत को लगभग 8 लाख रुपये के रूप में सूचीबद्ध किया है।

देवुसिंह चौहान; संचार: गुजरात के अपने लोकसभा क्षेत्र खेड़ा में नडियाड में 5.79 एकड़ कृषि भूमि, उनकी पत्नी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को 30.43 लाख रुपये में। डॉ महेंद्र मुंजपारा; महिला और बाल विकास- गुजरात के सुरेंद्रनगर के अपने लोकसभा क्षेत्र में सायला में कृषि भूमि, 28 जून, 2020 को 42,500 रुपये में। डॉ एल मुरुगन; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी- तमिलनाडु के नमक्कल जिले में उनकी पत्नी द्वारा 2 जुलाई, 2020 को 5.73 लाख रुपये में गैर-कृषि भूमि की ख़रीद की घोषणा की।

असली आंकड़े कहीं अधिक है

मंत्रियों द्वारा खरीदी गयी जायदादों के जो आंकड़े दिये गये हैं व पूर्णतया: आधे अधूरे हैं। जायदादों की दर्शायी गयी कीमत केवल सर्कल रेट के अनुसार है। सर्वविदित है कि किसी भी जायदाद की असल कीमत सर्कल रेट से कहीं अधिक होती है। इसके अलावा दर्शायी गयी जायदादे केवल वहीं है जिन्हें घोषित किया जाना आवश्यक था यानी कि छुपायी नहीं जा सकती थी। इसके अतिरिक्त जो अघोषित एवम् बेनामी जायदादें है उनके कोई आंकड़े दर्शाये नहीं गये हैं।

स्थानीय सांसद एवम् केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूर्जर की संपत्ति केअसल आंकड़े यद्यपि उपलब्ध नहीं है, फिर भी समय-समय पर इनकी अनेकों संपत्तियों का विवरण विभिन्न अखबारों में प्रकाशित किया गया है। और इनकी संपत्ति एकत्रित करने की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। कहने को बेशक ये जनप्रतिनिधि एवम् केन्द्रीय मंत्री है परन्तु वास्तव में न तो इनका जनता से कुछ लेना-देना और न ही मंत्रालय से; इनका असल मकसद सत्ता के सहारे अपनी संपत्तियों का विस्तार करना है।

कश्मीर पर पूरी तरह से नाकाम हो गया केंद्र

सुसंस्कृति परिहार

पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर फिर चर्चाओं में शुमार है। कहते हैं यहां अच्छा खासा पर्यटन चालू था लोग बड़ी तादाद में कोरोना से मुक्ति के बाद तफरी करने जा रहे थे कि इस बीच कुछ गैर कश्मीरियों को जिस तरह अकारण मारने का सिलसिला शुरू हुआ है उसने वादिए कश्मीर के बारे में फिर सोचने विचारने को बाध्य किया है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि अब तक कुल 28 लोग मारे गए हैं। इनमें से तीन कश्मीरी पंडित, एक सिख और दो प्रवासी मज़दूर हैं। बाक़ी 21 कश्मीरी मुस्लिम नागरिक हैं। इसलिए यह कहना कि गैर कश्मीरी या गैर मुस्लिम मारे गए गलत होगा। यह कहना तो सरासर झूठ है कि पंडितों का पलायन करने के लिए यह किया जा रहा है। जबकि वहां पंडित, सिख, मुस्लिम भाई चारा पूर्ववत जारी है यहां तक कि बड़ी संख्या में प्रवासी लोग भी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। इन घटनाओं से दहशत तो फैलती है पर कश्मीर कई दशकों से इस दर्द को अपने दामन में सहेजे हुए है।

मगर प्रश्न तो इस बात का है कि धारा 370 हटाने के वक्त जो बातें कहीं गई थीं उसे तीन साल से ज्यादा होने के बावजूद पूरा नहीं किया गया। इतनी अधिक सुरक्षा घेरे के बावजूद कश्मीर के लोग आज भी वही दंश झेल रहे हैं जो पहले झेलते रहे हैं। ये ज़रूर हुआ है कि वहां के लोगों से एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया और उसके टुकड़े कर दिए। केन्द्र शासित राज्य होने के बावजूद विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सके हैं। बाहर से आतंकी आकर अभी भी बराबर वारदात करते जा रहे हैं। अमन-चैन और मौलिक अधिकारों का हनन बराबर जारी है। अडानी ने कश्मीर के बागों में पैदा होने वाले बादाम, अखरोट, जाफ़रान और सेब फलों के साथ ही गुलज़ार चमनों की रंगत छीन ली है।

कश्मीर के ख़ूबसूरत पर्यटन पर भी इनकी नज़र है। जन्नत को व्यापार केन्द्र बनाने में केंद्रीय सरकार लगी हुई है। जबकि यहां के अवाम के दिलों में आज भी अपने कश्मीर वतन की आरज़ू है क्योंकि वे ना तो भारत में शामिल होना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान में। भारत के प्रति वे उदार हैं और उसे उसी रूप में देखना चाहते हैं जो उन्हें 370धारा के तहत छूट मिली थी। आपको याद होगा जब कश्मीर महाराजा हरिसिंह ने भारत से करार किया था तब कश्मीर में उनका झंडा तिरंगे के साथ फहराता था और शेख अब्दुल्ला तक प्रधानमंत्री कहलाते रहे। बाद के वर्षों में हुए कांग्रेस काल में समझौते के बाद मुख्यमंत्री कहलाने लगे। कुछ शर्तों के साथ भारत का कश्मीर एक पूर्ण राज्य बना। लेकिन उसी अवाम के साथ पांच अगस्त 2019 को जिस तरह छल और बल से वहां से 370 को हटाया उससे अवाम को गहरा आघात लगा है। यह काम प्रेम और सद्भाव से चुनी हुई सरकार के ज़रिए होता तो बात दूसरी होती।

बहरहाल,अब यह बात तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी महसूस कर ली है कि इस धारा को हटाने का सुफल नहीं मिला है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे पर कहा कि अनुच्छेद 370 जा चुकी है, लेकिन क्या यह दिमाग से निकल गया है? अब हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है। उधर समीपवर्ती अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन के आगमन से आतंकवाद को कश्मीर में घुसपैठ का एक मौका मिला है। पाकिस्तान भी मौके की तलाश में उनका सहयोग करेगा ही। यह हम भली-भांति जानते हैं। इस सबसे भी बड़ा अमेरिका से है क्योंकि वे केंद्र की कमज़ोर सरकार के मददगार बनकर इराक, अफगानिस्तान की तरह भारत के इस महत्वपूर्ण भाग पर नज़र रखे हुए हैं।

संभवत: चुनाव करीब हैं इसीलिए मोहन भागवत ने भी गिरगिट की तरह बदलाव लाते हुए यह कहा है कि हमें अब

मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। इसलिए ही वे मुस्लिमों को अपना पूर्वज और एक डीएनए का बताने को बाध्य हुए हैं। लिंचिंग करने वाले को हिंदुत्व के खिलाफ बता रहे हैं। अब वे ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को बढ़ाए, लेकिन ऐसी संस्कृति चाहते हैं, जो राष्ट्र को एक साथ बांधे और प्रेम को बढ़ावा दे। हिंदू-मुस्लिम के साथ के बिना भारत नहीं जैसी लोक लुभावन बात आजकल वे कह रहे हैं।

इन तमाम बातों के आईने में उभरते इस डरावने अक्स को मिटाने भारत सरकार को शीघ्र दो कदम उठाने की ज़रूरत है कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें और विधानसभा चुनाव शीघ्र कराएं ताकि राज्य की अवाम का भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कायम हो और वे भारत के साथ मिलकर अपनी चुनी हुई सरकार की इच्छानुसार अपने राज्य का विकास कर सकें। जन्नत में लूट और व्यापार की जगह ख़ूबसूरत घाटी को और हसीन रंगों में बदल सकें। ज़ोर ज़बरदस्ती से किए काम ज्यादा दिन नहीं टिकते। जनमत और उनका अभिमत मायने रखता है।